

संपादकीय

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता

श भर में सड़कों पुलों रेल-बस स्टेशनों हवाई अड्डों आदि का निर्माण तो तेजी से हो रहा है लेकिन क्या उनके निर्माण मानकों पर खतरे उत्तर पा रहे हैं? उचित यह होगा कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी यह देखें कि उनकी ओर से जिस भी आधारभूत ढाँचे का निर्माण कराया जा रहा है उसकी उपनिवेश से कोई समझौता तो नहीं हो रहा है? चंद दिनों पहले लू से झुलसती दिल्ली अब बारिश के कारण बेहाल है। यह स्थिति इसीलिए बनी, क्योंकि कम समय में कहीं अधिक बरसात हो गई। इसके चलते जगह-जगह जलभराव होने से जनजीवन तो अस्त-व्यस्त हुआ ही, दिल्ली एयरपोर्ट के एक हिस्से की छत गिर जाने से एक व्यक्ति नींजा जान भी चली गई। इस घटना को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

आवश्यकता तो उन कारणों का निवारण करने की है, जिनके चलते जगह-जगह जलभराव के साथ एयरपोर्ट पर हादसा हुआ। अत्यधिक बरसात के कारण जो स्थिति

जलभरात के साथ एपरेटर पर हादसा हुआ। अत्यधिक बरसात के कारण जा स्थित देल्ली में बनी, वैसी देश-दुनिया के अन्य शहरों में भी रह-रहकर बनती ही रहती है। इसके कुछ समय पहले आधारभूत ढांचे की वृष्टि से कहीं अधिक उन्नत शहर दुबई सामान्य से अधिक बरसात के चलते पानी-पानी हो गया था। पिछले कुछ वर्षों में अपने देश में भी अत्यधिक बरसात के चलते बेहतर आधारभूत ढांचे वाले शहर भी गंभीर समस्याओं से घिरते रहे हैं। अब जब जलवायु परिवर्तन के कारण भौसम में अप्रत्याशित बदलाव एक यथार्थ है, तब फिर यह समझा जाए कि इस बदलाव जनित समस्याओं पर जगनीतिक तू-तू मैं-मैं से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भौसम में अप्रत्याशित बदलाव के कारण भीषण गर्मी अथवा ठंडे के चलते जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उनका सामना आसान नहीं, लेकिन कम से कम ऐसे उपाय तो किए ही जा सकते हैं, जिससे अत्यधिक बरसात जनित समस्याओं से पर पाया जा सके। यह तभी संभव हो सकेगा, जब सरकारें दूरगामी उपायों पर ध्यान केंद्रित करेंगी और आम जनता भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार रहेंगी।

जब भी कहीं आवश्यकता से अधिक बरसात हो जाती है तो आधारभूत ढांगे की पोल खुल जाती है। इस्थिति यह है कि एक-दो वर्ष पहले किए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी गम्भीर सवाल खड़े हो जाते हैं। इन सवालों को लेकर राजनीतिक दल एक-दूसरे को ऐसे धरने लगते हैं, जैसे उनके दल द्वारा शासित राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों की ओर से कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की साक्षित हो रही हो। इस सच से मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं कि वाहे राज्य सरकार की एजेंसियों की ओर से किए गए निर्माण कार्य होंगे या किफर केंद्र सरकार की एजेंसियों के, उनकी गुणवत्ता कसौटी पर खरी नहीं उतरती। अपने देश में जैसे नई बनी सड़कें बढ़-रहकर धंसती रहती हैं, वैसे ही नए बने पुल भी गिरते रहते हैं।

जो रहा है, लाफन पदा उनके निमाने नानका पर खार डार पा रहा है ? तो पदा पह हाजा किए के कंद सरकार के साथ राज्य सरकारें भी यह देखें कि उनकी ओर से जिस भी आधारभूत ढाँचे का निर्माण कराया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता से कोई समझौता तो नहीं हो रहा है ?

**ਦੌੰਸੇਕਸ ਪਹਲੀ ਬਾਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ
ਪਾਰ, ਨਿਪਟੀ 24,300 ਕੇ ਊਪਰ**

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार के लिए गुरुवार का कारोबारी सत्र काफी उत्तर-चढ़ाव वाला रहा। बाजार के मुख्य सूचकांक हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। दिन के दौरान सेसेक्स और निफ्टी ने क्रमशः 80,392 और 24,401 का नया ऑल-टाइम हाई बनाया। लेकिन, ऊपरी स्तरों पर बाजार टिकने में विफल हुआ। कारोबारी सत्र के अंत में सेसेक्स 62 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 80,049 और निफ्टी 15 अंक या 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,302 पर था। यह पहली बार है जब सेसेक्स 80,000 के ऊपर बंद हुआ है। लाजकेप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में बढ़त देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 325 अंक या 0.58 प्रतिशत की बढ़त के साथ 56,618 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 92 अंक या 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,792 पर बंद हुआ। सेसेक्स पैक में टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक, आर्डिसीआर्डिसीआर्ड बैंक, सन फार्मा,

दैनिक करंट क्राइम

समाचार पत्र में किसी भी तरह के डिस्प्ले एवं वर्गीकृत विज्ञापन (खोया-पाया, संबंध-विच्छेद, कोर्ट नोटिस, जीडीए सूचना, नाम परिवर्तन) आदि के लिए निम्न फोन नंबर एवं पते पर संपर्क करें।

पाठकों, आप भी हमें भेज सकते हैं अपनी लिखी हुई कविता, चुटकुले, विचार, आर्टिकल या फोटो जैसे काम आपकी नाम पर दिए गए बोर्ड पर दर्शाया जाएगा।

अब यूएई में यूपीआई के जरिए¹ कर सकेंगे डिजिटल भुगतान

नई दिल्ली। अब आसानी से मध्य पूर्व के देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में यूपीआई से भुगतान किया जा सकेगा। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की बड़ी डिजिटल कॉर्सस कंपनी नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है यूई में अब भारतीय यात्री या एनआरआई पॉइंट ऑफ सेल मशीन के माध्यम से क्यूआर कोड के जरिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) भुगतान कर पाएंगे। एनपीसीआई इंटरनेशनल के सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा कि यूएई के मर्चेंट्स के बीच यूपीआई पेमेंट की बढ़ती हुई स्वीकार्यता केवल भारतीय यात्रियों के लिए ही नहीं



सुविधाजनक होगा, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेटिव डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को भी प्रमोट करेगा। एनपीसीआई ने कहा है कि 2024 में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) में भारतीय यात्रियों का आंकड़ा 98 लाख पहुंचने का अनुमान है। अकेले यूएस 53 लाख के करीब भारतीयों के पहुंचने की संभावना है। भारत सरकार, भारत रिजर्व बैंक (आरबीआई) और एनपीसीआई इंटरनेशनल मिल यूरीआई को वैश्विक मंच पर बढ़ावा

के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल भारत के बाहर नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, यूपीआई से भुगतान किया जा सकता है। यूपीआई से डिजिटल भुगतान आसान होने के कारण इसके जरिए होने वाले लेनदेन की संख्या में साल दर साल इजाफा हो रहा है। एनपीसीआई के डेटा के मुताबिक, यूपीआई प्लेटफॉर्म पर जून में लेनदेन की संख्या 13.9 अरब थी। इसमें सालाना आधार पर 49 प्रतिशत का इजाफा देखा गया है। इस दौरान यूपीआई से औसत लेनदेन की संख्या प्रतिदिन 463 मिलियन रही और प्रतिदिन औसत 66,903 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ।

भारत दुनिया के तीन सबसे आशावादी देशों में शामिल : सर्वे



है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। पिछले सर्वे के मुकाबले महंगाई और बेरोजगारी की चिंता में क्रमशः 3 और 9 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो महंगाई को लेकर 33 प्रतिशत,

ਅਥਿਂ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ : ਸਰੋ

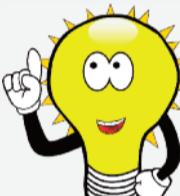
जुर्म और हिंसा को लेकर 30 प्रतिशत, गरीबी और सामाजिक असमानता को लेकर 29 प्रतिशत बेरोजगारी को लेकर 27 प्रतिशत और वित्तीय एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार को लेकर 25 प्रतिशत लोगों चिंतित हैं। आईपीएस ओएस ऑनलाइन पैनल सिस्टम के तहत सर्वे 24 मई, 2024 से लेकर 7 जून, 2024 के बीच किया गया है। इसमें 29 देशों के 25,520 व्यक्ति लोगों से जानकारी एकत्रित की गई है। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा जैसे देशों में सैपल साइट करीब 1,000 का रहा है। जबकि, भारत, अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और इजराइल जैसे देशों में सैपल साइट 500 का रहा है।

**इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के
लिए आईटी मंत्रालय ने दिया 44 हजार
करोड़ रुपये की सहायता का सुझाव**



नई दिल्ली। भारत सरकार का जोर सेमीकंडक्टर के साथ घेरलू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावें पर है, जिससे देश को दुनिया के सलाई चेन हब के रूप में विकसित किया जा सके। इसके लिए आईटी मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसने सरकार को सुझाव दिया है कि घेरलू कंपनियों को 2030 तक 44,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाए। मंत्रालय की ओर से इस टास्क फोर्स का गठन इस वर्ष जनवरी में किया गया था। इसका नेतृत्व अजय कुमार सूद कर रहे हैं, जो कि सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इसके अलावा अन्य सदस्य जैसे एचसीएल के संस्थापक और ईपीआईसी फाउंडेशन के चेयरमैन अजय चौधरी और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के एमडी सुनील वचनी इस टीम के सदस्य हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, टास्क फोर्स ने प्रोडक्शन-लिंकड ईंस्ट्रिटिव (पीएलआई) स्कीम को 2030 तक बढ़ावें की सिफारिश की है। इससे एप्ल जैसी कंपनियों को भारत में आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिलेगी और निर्यात बढ़ेगा। चौधरी ने कहा कि इसका मकसद भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स आयात बिल को कम करना है। उन्होंने आगे कहा कि अगले पांच वर्ष भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी अहम होंगे इससे अगले कई दशकों की दिशा तय होगी। हमें एक उत्पादक देश बनाना है और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स में चीन को कड़ी टक्कर देनी है। इसके लिए देश के अपने सबसे अच्छे लोगों को आगे लाना होगा। टास्क फोर्स के सदस्यों के मुताबिक, सरकार ने पिछले 10 वर्षों में युनिक्षित किया है कि भारतीय कंपनियां खुद को पुनर्जीवित करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भार' अभियान के तहत लिए गए एक क्षण को जमीनी स्तर पर काफी सराहना मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब हमारा फोकस वैल्यू-एडेक्ड मैन्युफैक्चरिंग और भारत में उत्पादों के डिजाइन पर होना चाहिए। इसके जरिए भारत ग्लोबल ब्रॉडबैंड के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत कर सकता है।

रोचक तथ्यों का करंट



- अजवाइन को खाने में कितनी कैलोरी लगती है जितनी की अजवाइन से आपको कैलोरी नहीं मिलती।
- तोते इंसानों की तरह अपने बच्चों को एक नाम देते हैं। और उम्र भर उनका वही नाम रहता है।
- इंसान के दिमाग का विकास 40 साल की उम्र तक तक होता है।
- अगर कोई आपको अपनी सपने के बारे में बताएं तो यह जरूर पूछना कि उसका सपना कहां से शुरू हुआ, क्योंकि सपना कहां से शुरू हुआ यह बताना पॉसिबल नहीं।
- दुनिया का 70% उपयोग किए जाने वाले मसाले भारत में ही तैयार होते हैं।
- एक गधा रेत के दलदल में ढूब सकता है परंतु एक खच्चर नहीं रुक सकता है।
- इंसानों की तरह तोते भी मोटापे की बीमारी का शिकार होते हैं।
- जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय माँ को होने वाला दर्द एक साथ 20 हड्डियां टूटने के बराबर होता है।
- कोई भी व्यक्ति अपनी सांस रोककर अपने आप को नहीं मार सकता।

करंट क्राइम

परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शभकामनाएं

आज के जन्मदिन



